B.A 2
Paper IVth

सार्वजनिक व्यय के प्रकार :-
(Kinds of public expenditure)

सार्वजनिक व्यय के लिए वर्गीकरण की प्रथा काफी पुरानी है। सार्वजनिक व्यय का अर्थव्यवस्था पर अति गहरा प्रभाव पड़ता है; जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त सरकार का व्यय अर्थव्यवस्था के कुल व्यय का एक बड़ा अनुपात होता है और लगभग सभी देशों में इस अनुपात के बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अत: यह आवश्यक समझा जाता है कि सरकार अपने बजट को एक सुव्यवस्थित ढंग से तैयार तथा कार्यान्वित करे। इन कारणों से कालान्तर में बजट को कई प्रकार से वर्गीकृत करने की विधियाँ भी निकाली गई हैं जिनसे इससे संबंधित विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता मिलने की आशा की जाती है। इन वर्गीकरणों के मुख्य प्रकारों की संक्षिप्त व्याख्या निम्नलिखित है -

1. लेखाविधिक वर्गीकरण (Accounting classification) — सार्वजनिक व्यय का लेखाविधिक वर्गीकरण सैकड़ों वर्ष पुराना है। इसका मुख्य औचित्य इस तथ्य में निहित है कि सरकार की प्राप्तियाँ तथा संवितरण अति जटिल मद-समूह होती हैं। सार्वजनिक व्यय पर प्रभावी नियंत्रण रखना, घोटालों से तथा अपव्यय से बचाव करना, राशियों को अनधिकृत मदों पर व्यय किए जाने से रोकना आदि लोक व्यय के जटिल परंतु अति आवश्यक उद्देश्य हैं। एक प्रभावी नियंत्रण प्रणाली के बिना यह कार्य संभव नहीं है विशेषकर इसलिए कि एक आधुनिक सरकार की गतिविधियाँ बहुत विस्तृत हो चुकी हैं। लेखाविधिक वर्गीकरण द्वारा यह नियंत्रण कार्य संभव और सुगम हो जाता है।

2. हस्तांतरण तथा गैर-हस्तांतरण व्यय (Transfer and Non-Transfer Expenditure) — इस वर्गीकरण का सुझाव प्रो. पीगू ने दिया था। आर्थिक विश्लेषण के दृष्टिकोण से यह वर्गीकरण काफी लाभदायक है। यह राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी (national economic accounting) के अतिरिक्त अन्य बजटीय आँकड़ों की तैयारी में भी काम आता है। हस्तांतरण व्यय से

Scanned by CamScanner

अभिप्राय उन व्यय-मदों से है जिनके बदले में सरकार को कि प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं की प्राप्ति न होती हो। अर्थात् ये अदायगियाँ क्रय की गई वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमत के रूप में नहीं की जातीं। इन आदायगियों में उपदान, अनुदान पेंशनें, बेरोजगारी भत्ते तथा ब्याज आदि शामिल हैं।

3. राजस्व व्यय एवं पूँजी व्यय (Revenue and Capital Expenditure) – इस वर्गीकरण का तर्कद्वार यह है कि सरकार को अपने सामान्य दैनिक खर्चे नियमित राजस्व प्राप्तियों से ही पूरे करने चाहिए। इन व्यय-मदों के लिए उधार लेना तथा इस कारण ऋणी हो जाना ठीक नहीं है। उधार लेने का औचित्य तभी बनता है जब उसका उपयोग परिसंपत्ति -यों में बढ़ोतरी अथवा अन्य प्रकार से निवेश के वित्त-पोषण के लिए किया जाए। पूँजी व्यय में वे मदें आती हैं जिनसे सरकार अपनी परिसंपत्तियों में वृद्धि अथवा देयताओं में कमी लाती है।

4. उपभोग व्यय तथा पूँजी व्यय (Consumption Expenditure and Capital Expenditure) – यद्यपि यह वर्गीकरण एक प्रकार से राजस्व व्यय और पूँजी व्यय के वर्गीकरण का ही दूसरा रूप है, तो भी इसमें विशेषतौर पर पूँजी निर्माण के आयाम को उभारा जाता है। इस वर्गीकरण में सरकार प्रत्येक व्यय-मद के लिए यह निर्णय लेती है कि इसका उद्देश्य उपभोग अथवा पूँजी निर्माण में से कौन-सा है।

5. आयोजना-तथा आयोजना-भिन्न व्यय (Plan and Non-Plan Expenditure) – भारत में आयोजना-बद्ध आर्थिक विकास के प्रयास के फलस्वरूप सार्वजनिक व्यय को भी आयोजन व्यय और आयोजना-भिन्न व्यय वर्गों में विभाजित किया जाता है। जब किसी परियोजना (अथवा स्कीम) को आयोजना के अंतर्गत चुन लिया जाता है, तो परियोजना को पूरा हो जाने तक (अथवा स्कीम के पूरी तरह से लागू हो जाने तक) उस पर किए गए व्यय को आयोजना-व्यय कहा जाता है। इसी प्रकार परियोजना के पूरा हो जाने पर अथवा स्कीम के पूरी तरह लागू हो जाने के पश्चात् उस पर किया जाने वाला व्यय आयोजना-भिन्न व्यय कहलाता है। परंतु वर्गीकरण का यह सैद्धांतिक आधार विवादास्पद है।

Scanned by CamScanner

6. उत्पादक तथा गैर-उत्पादक व्यय (Productive and Non-Productive Expenditure) - एक मतानुसार लोक व्यय की कुछ मदें उपभोग रूपी होने के कारण गैर-उत्पादक (non-productive) होती हैं, जबकि कुछ अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के कारण उत्पादक (productive) अथवा 'निवेश व्यय' (investment expenditure) कहलाने की अधिकारी होती हैं। अहस्तक्षेप नीति के अनुसार बहुत थोड़ी व्यय मदों को 'उत्पादक' वर्ग में रखा जा सकता है, जैसे कि सामाजिक अवसंरचना (social overheads) के सृजन तथा रख-रखाव की व्यय मदें आदि। परंतु अब इस मत की स्वीकार्यता बढ़ती जा रही है कि प्रतिरक्षा, शिक्षण-प्रशिक्षण, न्याय, कानून तथा व्यवस्था जैसी कई मदों पर किया गया व्यय भी उतना ही उत्पादक होता है जितना कि कुछ अन्य मदों पर। इस मतानुसार गैर-उत्पादक व्यय केवल वह है जो समाज और अर्थव्यवस्था के विकास के लिए अनावश्यक हो, अथवा जिसे कार्यक्षमता के अभाव में अपव्यय माना जा सके।

7. आर्थिक तथा कार्यात्मक वर्गीकरण (Economic and functional classification) - इस वर्गीकरण का विस्तृत वर्णन एक अन्य अध्याय में किया गया है। यहाँ पर इतना कहना ही पर्याप्त है कि जब लोक व्यय को विभिन्न अर्थयुक्त आर्थिक मदों में विभाजित किया जाए तो इसे व्यय का आर्थिक वर्गीकरण (economic classification) कहा जाता है। इस वर्गीकरण द्वारा बजटीय मदों से संबंधित विभिन्न प्रकार के आर्थिक घटकों (जैसे कि निवेश, बचत, उपभोग, वित्तीय परिसंपत्तियाँ तथा देनदारियाँ) की जानकारी मिलती है। इसी प्रकार कार्यात्मक वर्गीकरण (functional classification) में व्यय-मदों का चयन सरकार के विभिन्न कार्यकलापों के आधार पर किया जाता है। इससे यह जानकारी मिलती है कि सरकार किस प्रकार की सेवाएँ मुहैया कर रही है।

8. लिंगाधारित वर्गीकरण (Gender-based classification) - यह वर्गीकरण नए उभरी आने वाली वर्गीकरण विधियों में से एक है, और इसे कई अन्य देशों सहित भारत में भी चरणबद्ध ढंग से अपनाया जा रहा है। इस वर्गीकरण में

Scanned by CamScanner

यह अनुमान लगाने का प्रयत्न किया जाता है कि लोक व्यय से स्त्रीलिंग कहाँ तक लाभान्वित हो रहा है; तथा इससे प्राप्त जानकारी के आधार पर लोक व्यय के आकार - प्रकार और नीति में किस प्रकार के सुधार की आवश्यकता है। उदाहरण हेतु भारत में महिला वर्ग के शिक्षण - प्रशिक्षण की नीति की प्रभाविता को बढ़ाने के लिए इस वर्गीकरण से प्राप्त जानकारी का प्रयोग किया जा सकता है।

Scanned by CamScanner